त्रिलोचन सिंह बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक
एक और (ए एल बहरी, जे।

न्यायमूर्ति ए एल बहरी *के समक्ष*

त्रिलोचन सिंह, - याचिकाकर्ता।

बनाम

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1988 का 11741।

30 मई 1989।

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद *226 227*- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड-11, *1986* संस्करण, नियम *7, 21*- बीए परीक्षा में कंपार्टमेंट या जेलिंग के तहत रखे गए उम्मीदवार-^ऐसे

पूरक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवार - बीएड में अनंतिम रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवार. - बाद में पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार - बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश - क्या रद्द किया जा सकता है।

यह माना गया कि विश्वविद्यालय के वकील की यह दलील कि विचार के लिए प्रासंगिक समय पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख है और यदि किसी उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता में कमी है, तो उसे पढ़ाई जारी रखने और बीएड पाठ्यक्रम की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह बीएड छात्रों, याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के लोगों के लिए बहुत कठोर रूप से काम करेगा। याचिकाकर्ता, जो छात्र हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। यद्यपि उन्होंने पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम में भाग लिया है और सितम्बर, 1988 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम के लिए पात्र होने के कारण, इक्विटी घड़ी को उलटने और उन्हें प्रवेश के प्रारंभिक चरण में लाने की मांग नहीं करती है और यह कहने की मांग नहीं करती है कि चूंकि वे प्रवेश के लिए आवेदन दाखिल करते समय बीए नहीं थे। वे अब पाठ्यक्रम जारी नहीं रख सकते और अंतिम परीक्षा नहीं दे सकते। यह याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत कठोर रूप से काम करेगा, जिन्हें किसी भी स्तर पर स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिला। प्रवेश शुल्क स्वीकार करने वाला विश्वविद्यालय अब यह नहीं कह सकता कि ये याचिकाकर्ता बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय पात्र नहीं थे।

(पैरा 9 और 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका *में प्रार्थना की गई है कि:*

(1) परमादेश, परमाणपत्री या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की रिट जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया हो कि वे याचिकाकर्ता के बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द न करें क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही नामांकन संख्या 10 के साथ चुना जा चुका है। उत्तरदाताओं द्वारा पत्राचार के माध्यम से बीएड कोर्स के लिए *पीबी -44831।*

(2) इसके अलावा प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को लुधियाना, आर्य कॉलेज में उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित किए जा रहे व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दें। लुधियाना 26 दिसंबर 1988 से 6 जनवरी 1989 तक और उसके बाद याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने और अपना परिणाम घोषित करने की अनुमति देता है।

(3) प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस और अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकताओं को छूट दी जा सकती है।

(4) इस याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

(5) इस याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर *से प्रदीप गुप्ता, एडवोकेट।*

जे. एल. गुप्ता, सीनियर एडवोकेट और प्रतिवादी के लिए एडवोकेट विक्रांत शर्मा।

आदेश

ए. एल. बहरी, जे.

(1) *इस निर्णय के माध्यम से*, कई रिट याचिकाओं का निपटान किया जा रहा है। तर्क दिए गए प्रश्नों में से एक सभी रिट याचिकाओं में सामान्य है जो निम्नानुसार तैयार किया गया है: –

> "क्या जो छात्र बीए की अंतिम परीक्षा में अप्रैल में उपस्थित हुए थे या कंपार्टमेंट में रखे गए थे, वे बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं

और बाद में सितंबर में आयोजित बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं (पूरक परीक्षा)।

दो मामलों में तथ्य बताए जा रहे हैं जबकि अन्य मामलों में तथ्य समान हैं।

(2) सामान्य तथ्य निम्नानुसार हैं -

(3) एमडी विश्वविद्यालय ने सत्र 1989-89 में पहली बार बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया। यह एक वर्ष का पाठ्यक्रम है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई, 1988 थी जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है। प्रवेश पूरे देश के उम्मीदवारों के लिए खुला था जो अन्यथा विभिन्न कारणों से शिक्षा के कॉलेजों में प्रवेश करने में विफल हो सकते हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रॉस्पेक्टस के पृष्ठ -2 पर नोट निम्नानुसार है: –

> जिन उम्मीदवारों के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, वे शुल्क की पहली किस्त के बिना 31 मई को या उससे पहले प्रवेश फॉर्म जमा कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें फॉर्म के साथ योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। परिणाम की घोषणा की तारीख से दस दिनों के भीतर शुल्क जमा किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

पाठ्यक्रम के लिए शुल्क तीन किस्तों में देय है। पहली किस्त 31 मई, 1988 को या उससे पहले देय थी और प्रवेश फॉर्म के साथ पहली किस्त के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाना था। दूसरी किस्त 20 सितंबर, 1988 को या उससे पहले और तीसरी किस्त 18 फरवरी, 1989 को देय थी। अब उत्तरदाताओं का मामला यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किस्तों के भुगतान के लिए समय बढ़ाया गया था। प्रवेश पर, पंजीकरण कार्ड

और पहचान पत्र जारी किया जाना था। बीएससी (पास) परीक्षा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड -2, 1986 संस्करण में पृष्ठ -35 पर दी गई है। बीए (फाइनल) के तीन भागों के लिए, परीक्षाएं आयोजित की जानी थीं। भाग -1 परीक्षा पहले वर्ष के अंत में, भाग -2 दूसरे वर्ष के अंत में और भाग -3 तीसरे वर्ष के अंत में आयोजित की जानी थी। उसी वर्ष सितंबर के महीने में एक विषय या अन्यथा में फिर से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक पूरक परीक्षा आयोजित की जानी आवश्यक थी। इस अध्याय के नियम 7 का प्रासंगिक सार निम्नानुसार है:-

> "एक उम्मीदवार जो इस विश्वविद्यालय की परीक्षा के विषय में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र है, उसे अगली उच्च कक्षा में अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा।

इस अध्याय का नियम 20 बीए भाग -1 और भाग -2 परीक्षाओं में प्रवेश से संबंधित है जबकि इस अध्याय का नियम 21 बीए भाग -3 परीक्षा में एक विषय में असफल छात्र द्वारा एमए भाग -1 परीक्षा में अनंतिम रूप से शामिल होने का उल्लेख करता है।

(4)1988 के सी.डब्ल्यू.पी. सं.11117419 में *मैं (त्रिलोचनज सिंह* बनाम एम.डी.)*(v) विश्वविद्यालय और अन्य*, तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं: –

त्रिलोचन सिंह ने अप्रैल, 1988 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन *किया,*-— आवेदन, अनुबंध पी.एल. शुल्क की पहली किस्त बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी गई थी- पत्र के *माध्यम से*, अनुलग्नक पी.2. इस पत्र के साथ, बीए (अंतिम) परीक्षा का परिणाम कार्ड भी भेजा गया था। अनुबंध पी, 3 विश्वविद्यालय का परिणाम-सह-विस्तृत अंक कार्ड है। विश्वविद्यालय ने त्रिलोचन सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें अनुबंध पी.4 की प्रति, यह सूचित किया गया कि बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं हुआ है और बीस दिनों के भीतर शुल्क जमा किया जाना चाहिए; मूल अंक पत्र भी भेजा जाना चाहिए; डिग्री और विस्तृत अंक प्रमाण पत्र की दो प्रतियां भी भेजी जानी चाहिए। माइग्रेशन प्रमाण पत्र मांगा गया था। अनुलग्नक पी.5 उपर्युक्त पत्र का उत्तर है। यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय से मूल डिग्री प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन के साथ विस्तृत अंक पत्र संलग्न किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय से माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने का अनुरोध किया गया था। इस स्तर पर, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि त्रिलोचन सिंह ने बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए पंजाब विश्वविद्यालय का रुख किया था और बाद में उन्होंने एक विषय में कम्पार्टमेंट में रखा है। त्रिलोचन सिंह ने उसी वर्ष सितंबर में आयोजित पूरक परीक्षा में कम्पार्टमेंट पास किया। उक्त परीक्षा की विस्तृत मार्कशीट अनुबंध पी. 7 त्रिलोचन में

सिंह को प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम के नियमित रूप से लिखित निर्देश मिल रहे थे। यह पता चलने पर कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय कई छात्रों के प्रवेश को रद्द कर रहा है, जिन्होंने अप्रैल, 1988 में आयोजित बीए परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, इस रिट याचिका के साथ इस रिट याचिका के साथ इस रिट याचिका के साथ उत्तरदाताओं को बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में अपना प्रवेश रद्द नहीं करने का निर्देश देने के लिए संपर्क किया। विश्वविद्यालय की ओर से दायर लिखित बयान में आरोप लगाया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अप्रैल परीक्षा की विस्तृत अंक शीट प्रस्तुत की थी, जिससे पता चला कि उसने बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसलिए उसे बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में भर्ती कराया गया था। तथापि, अप्रैल, 1988 की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पर, उनके परिणाम को अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण से कम्पार्टमेंट तक संशोधित किया गया जैसा कि अनुलग्नक पी6 में दर्शाया गया है। उन्होंने पूरक परीक्षा में इसे पास किया। बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। इसलिए, याचिकाकर्ता वर्तमान सत्र में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता था क्योंकि उसने अप्रैल, 1988 में आयोजित बीए परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी।

(5) 1989 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 1381 में *(*राज बाला बनाम राजबाला एमडी विश्वविद्यालय और अन्य*),* तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं: –

(1) श्रीमती राजा बाला बीए की परीक्षा में शामिल हुईं। हालांकि, जब उसने एमडी विश्वविद्यालय के बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया तो उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया था। उसने बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश फॉर्म दाखिल किया। 25 जुलाई, 1988 के पत्र के माध्यम से, श्रीमती राजबाला को सूचित किया गया था कि जब उन्होंने बीएड पत्राचार न्यायालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया था तो डिग्री और विस्तृत अंक पत्र की दो सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। उसे बीस दिनों के भीतर किस्त शुल्क जमा करने के लिए भी कहा गया था। उसे पहचान पत्र जारी नहीं किया गया था और उसके पिता ने विश्वविद्यालय से संपर्क किया और उसे पता चला कि प्रतिवादी उसे प्रवेश नहीं दे रहे थे क्योंकि उसने सितंबर, 1988 में अंग्रेजी में अपना कम्पार्टमेंट पेपर पास किया था और इसलिए, प्रवेश के लिए पात्र नहीं था।

(7) अन्य मामलों के तथ्य समान हैं कि बीए परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान, उम्मीदवारों को कम्पार्टमेंट में रखा गया था। उन्होंने बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने रिट याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय का रुख किया और अब इस न्यायालय के आदेशों के तहत पाठ्यक्रम जारी रख रहे हैं। इन उम्मीदवारों ने सितंबर, 1988 में आयोजित पूरक परीक्षा में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की।

(8) यहां तक कि मामले के अजीब तथ्यों में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यदि यह माना जाता है कि त्रिलोचन सिंह को सही तरीके से प्रवेश दिया गया था क्योंकि उन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी और पुनर्मूल्यांकन के पाठ्यक्रम के

दौरान उन्हें कम्पार्टमेंट में रखा गया था और अंत में सितंबर, 1988 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें पढ़ाई जारी रखने और परीक्षा देने और इसे पास करने की अनुमति दी जाती है। अन्य रिट याचिकाओं में अन्य याचिकाकर्ताओं को समान राहत से इनकार करने का कोई कारण नहीं होगा क्योंकि यह भेदभाव होगा जो कानून द्वारा अनुमति नहीं है।

(9) विश्वविद्यालय के वकील का तर्क यह है कि विचार के लिए प्रासंगिक समय पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख है और यदि किसी उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता में कमी थी, तो उसे पढ़ाई जारी रखने और बीएड पाठ्यक्रम की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह बीएड छात्रों, याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के लोगों के लिए बहुत कठोर रूप से काम करेगा। याचिकाकर्ता, जो छात्र हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। यद्यपि उन्होंने पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम में भाग लिया है और सितम्बर, 1988 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण होने के कारण पाठ्यक्रम के लिए पात्र होने के कारण, इक्विटी घड़ी को उलटने और उन्हें प्रवेश के प्रारंभिक चरण में लाने की मांग नहीं करती है और यह कहने की मांग नहीं करती है कि चूंकि वे प्रवेश के लिए आवेदन दाखिल करते समय बीए नहीं थे। वे अब पाठ्यक्रम जारी नहीं रख सकते और अंतिम परीक्षा नहीं दे सकते। यह याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत कठोर रूप से काम करेगा, जिन्हें किसी भी स्तर पर स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिला। त्रिलोचन सिंह के मामले में, सब कुछ पूर्वोक्त पाठ्यक्रम में भर्ती होने के बाद हुआ यानी उन्होंने बीए परीक्षा पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया और पुनर्मूल्यांकन पर, उन्हें दो विषयों में कम्पार्टमेंट में रखा गया और आखिरकार उन्होंने सितंबर, 1988 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा के दौरान ही वह बीएड कोर्स में प्रवेश के योग्य हो गए। इस अवधि के दौरान, त्रिलोचन सिंह पाठ्यक्रम में भाग ले रहे थे। विश्वविद्यालय के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश पर आपत्ति उठाने में बहुत देर हो चुकी है, केवल इस आधार पर कि पाठ्यक्रम के लंबित रहने के दौरान, उसके परिणाम को संशोधित और पुन: संशोधित किया गया था यानी पहली बार संशोधित किया गया था जब उसने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था और पास से, उसे डिब्बे में रखा गया था और फिर से संशोधित किया गया था यानी कम्पार्टमेंट पेपरों की मंजूरी के बाद, याचिकाकर्ता को बीए परीक्षा में पास घोषित किया गया था। त्रिलोचन सिंह को बीएड कोर्स में अपनी पढ़ाई में मामले के अजीबोगरीब तथ्यों के कारण किसी भी मामले में पीड़ित नहीं होना है।

(10) कुछ याचिकाकर्ताओं को अस्थायी प्रवेश दिया गया था, हालांकि उन्हें कम्पार्टमेंट में रखा गया था और उन्होंने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। चूंकि इन याचिकाकर्ताओं का निधन हो चुका है

1987-88 के दौरान सितंबर में बीए परीक्षा और विश्वविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश शुल्क को स्वीकार किए जाने के बाद, अब विश्वविद्यालय यह नहीं कह सकता है कि ये याचिकाकर्ता बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय पात्र नहीं थे।

(11) विश्वविद्यालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एल.टी. गुप्ता की यह दलील कि केवल वे छात्र जिन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, बीएड पाठ्यक्रम के लिए पात्र थे, विश्वविद्यालय के बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रॉस्पेक्टस में दिए गए नोट को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त नोट विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के संबंध में अनंतिम प्रवेश पर विचार करता है जिन्होंने अंतिम परीक्षा दी थी और परिणाम 31 मई, 1989 तक घोषित नहीं किए गए थे, जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी। यहां तक कि बीए की अंतिम परीक्षा में भाग लेने के प्रमाण पर भी, उन्हें बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना था। एकमात्र सीमा यह है कि अंतिम परीक्षा के पूरा होने के बाद, अंकों की जांच के लिए विस्तृत अंक पत्र देखा जाना चाहिए जो परिणाम की घोषणा से दस दिनों के भीतर भेजा जा सकता है। इस प्रकार, नोट विशिष्ट है कि बीए परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना, बीएड पाठ्यक्रम में अनंतिम प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। विश्वविद्यालय कैलेंडर के पृष्ठ 38 पर मौजूद नियम 7, जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, भी उसी प्रभाव के लिए है। एक उम्मीदवार, जो बीए परीक्षा के विषयों में से एक में फिर से उपस्थित होने के लिए पात्र है, उसे अगली उच्च कक्षा में अनंतिम प्रवेश मिल सकता है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जेएल गुप्ता ने तर्क दिया कि नियम 7 केवल बीए भाग -2 और भाग -3 परीक्षाओं पर लागू होता है। मुझे डर है कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह नियम सामान्य है और अगली सभी उच्च कक्षाओं पर लागू होगा जहां बीए परीक्षा देने वाले व्यक्ति प्रवेश चाहते हैं। इस स्तर पर, बीए परीक्षाओं से संबंधित इस अध्यादेश के नियम 20 और 21 का भी संदर्भ दिया जा सकता है। नियम 20 से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह एक उम्मीदवार को संदर्भित करता है जो केवल बीए भाग -1 परीक्षा या भाग -2 परीक्षा में एक विषय में विफल रहता है क्योंकि वह अगली उच्च कक्षा यानी भाग -2 या भाग -3 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। नियम 21 में बीए पार्ट-III परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को एमए पार्ट-1 परीक्षा में अनंतिम प्रवेश देने का प्रावधान है। मुझे बताया गया था कि बीए परीक्षा में कम्पार्टमेंट प्राप्त करने पर लॉ कोर्स में प्रोविजनल एडमिशन भी किया जाएगा। जैसा भी हो, बीए परीक्षा से संबंधित नियमों यानी नियम 7 का अवलोकन करने पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बीएड पाठ्यक्रम परीक्षा में अनंतिम प्रवेश हो सकता है। यही स्थिति है, केवल तथ्य यह है कि रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान आखिरकार याचिकाकर्ताओं ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की।

सितंबर में उन्हें बीएड परीक्षा में पाठ्यक्रम पूरा करने का अधिकार दिया जाएगा। छात्रों के हित को केवल तकनीकी पर खतरे में नहीं डाला जा सकता है यानी वास्तव में उन्होंने बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय बीए परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी।

(12) प्रतिवादियों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जेएल गुप्ता ने अध्यादेश-बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) में नियम 3 का उल्लेख किया है। विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1986 संस्करण, खंड-II में पृष्ठ 107 पर उल्लिखित परीक्षा। इस नियम के अनुसार, कम से कम चालीस प्रतिशत अंकों के साथ बीए / बीएससी की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र बनाया गया था। वकील के अनुसार, एक असफल उम्मीदवार या कम्पार्टमेंट केस उम्मीदवार पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले ही देखा गया है, पूरक परीक्षा में एक ही परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक उम्मीदवार को अधिकार दिया जाता है। यह अधिकार इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी आगे की पढ़ाई प्रभावित न हो और एक साल का श्रम बेकार न जाए। अनंतिम प्रवेश पूरक परीक्षा में बीए (अंतिम) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार के अधीन है। पूरक परीक्षा में बीए उत्तीर्ण करने पर, उम्मीदवार हमेशा बीएड कोर्स के लिए पात्र रहा।

(13) याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को प्रवेश की अनुमति देने के बाद, उन्हें कोई नोटिस दिए बिना इसे रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुनवाई के अवसर के बिना कोई कानूनी अधिकार नहीं छीना जा सकता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने *पूर्व कैप्टन केसी अरोड़ा और अन्य* मामले में कहा था।*हरियाणा राज्य और अन्य* (1). *राम सरूप* वी। *हरियाणा राज्य और अन्य* (2), एक ऐसा मामला था जहां आवेदक के पास नियुक्ति के समय अपेक्षित योग्यता नहीं थी, हालांकि, आक्षेपित आदेश पारित करने के समय, उसने अपेक्षित योग्यता / अनुभव प्राप्त किया था, याचिकाकर्ता, यह आरोप लगाया गया था, को वापस नहीं किया जा सकता था। इन मामलों में निर्णय के अनुपात का कुछ हद तक पालन किया जा सकता है। आगे *हरिंदर कौर चंडोक बनाम इस* न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। *पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड* (3)। उम्मीदवार मार्च, 1986 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में असफल रहा था। उसने सितंबर में इसी परीक्षा को पास किया था। 1986. उसे आगे -जे -1 परीक्षा देने की अनुमति दी गई। यह माना गया था कि उसकी परीक्षा इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि दो परीक्षाओं यानी सितंबर, 1986 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा और -जे -1123 के बीच एक वर्ष की अवधि

(1) 1984 (2) एसएलआर 97.
(2) 1978 (2) एसएलआर 836।
(3) ए.आई.आर. 1988 पंजाब और हरियाणा 244.

अप्रैल 1987 में आयोजित परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। यह इस मामले में था कि यह माना गया था कि पूरक परीक्षा की कोई उपयोगिता नहीं थी यदि उम्मीदवार इसे पास करने के बाद एक वर्ष नहीं बचा सकता था। निर्णय के पैरा 5 में, यह निम्नानुसार देखा गया था:

> "शुद्ध परिणाम यह होगा कि भले ही कोई छात्र सितंबर, 1986 (पूरक परीक्षा) में मैट्रिक उत्तीर्ण कर चुका हो, लेकिन पूरक परीक्षा पास करने का उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि वह पूरे एक साल बर्बाद करने के बाद अप्रैल, 1987 की वार्षिक परीक्षा में भी उपस्थित हो सकता था। इससे बोर्ड द्वारा पूरक परीक्षा आयोजित करने की कवायद पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी।

(14) *हरिंदर कावए चंडोक मामले* में उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा *अंजना गुलाटी, नाबालिग थ्रू फादर* वी *मामले में खारिज कर दिया गया था।* पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (4) ने इस आधार पर कि शुरू में प्रवेश नहीं मांगा जा सकता था क्योंकि उम्मीदवार ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा, भाग -1, विनियम, 1986 के विनियमन 5 के तहत प्रदान किए गए एक शैक्षणिक वर्ष पहले नहीं बिताया था। उपर्युक्त विनियम का सार निम्नानुसार है: -

> *"परीक्षा के लिए पात्रता:*
>
> एक। वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा भाग -1 एक ऐसे व्यक्ति के लिए खुला होगा जिसके पास है। कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष पहले उत्तीर्ण:
>
> (1) इस बोर्ड की मैट्रिक या माध्यमिक विद्यालय परीक्षा।
>
> (2) ऊपर (i) में उल्लिखित परीक्षाओं के समकक्ष बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा....."'

डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार कहा: -

> "हालांकि विनियम 5 में निहित प्रावधान, विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए तर्क पर, कारण प्रतीत होता है

(4) 1988 (3) एस, एल * आर 748।

> सितंबर में आयोजित मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को कुछ कठिनाई होती है, लेकिन उस स्कोर पर इसे मनमानी शर्त लगाने या रद्द करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

राजेंद्र प्रसाद माथुर *बनाम* सुप्रीम कोर्ट का फैसला *कर्नाटक विश्वविद्यालय और एक अन्य* (5), *अंजना गुलाटी के मामले* (सुप्रा) में तथ्यों के आधार पर प्रतिष्ठित थे। *राजेंद्र प्रसाद माथुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट* ने निम्नानुसार कहा: –

> पीठ ने कहा, "हमें समझ नहीं आता कि अपीलकर्ताओं को इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रबंधन के पापों के लिए क्यों भुगतना चाहिए। इसलिए, हम इस फैसले में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के बावजूद, अपीलकर्ताओं को संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हैं, जिसमें उन्हें प्रवेश दिया गया था।

उपरोक्त टिप्पणियों को उच्चतम न्यायालय ने *ए सुधा* बनाम भारत मामले में आधार बनाया था।*मैसूर विश्वविद्यालय* 0/*मैसूर और दूसरा* (6), और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: –

> "इसलिए, अदालत का विचार था कि चूंकि छात्र निर्दोष थे और कुछ मामलों में कैपिटेशन शुल्क के लिए कॉलेजों में भर्ती हुए थे, इसलिए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसमें उन्हें प्रवेश दिया गया था।

मिस पूनम कुमारी बनाम *कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एक अन्य* (7), जिसमें पूनम कुमारी के पूरा कोर्स पूरा करने के बाद बीएड कोर्स में प्रवेश रद्द कर दिया गया था, विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया था कि वह अपना परिणाम तुरंत घोषित करे ताकि उसके छात्र करियर की काफी अवधि बर्बाद न हो।

(15) ऊपर चर्चा किए गए विवरणिका और विवरणिका में दिए गए विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही न्यायसंगत आधार पर ऊपर चर्चा किए गए निर्णयों के अनुपात पर आधारित है, हाथ में लिए गए मामलों का निपटान किया जाना है। बीएड पत्राचार में प्रवेश के लिए जारी प्रॉस्पेक्टस में

(5) ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 1448.

(6) ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 2305.

(7) 1987 के सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 6929 पर 25 जुलाई, 1988 को निर्णय लिया गया।

पाठ्यक्रम, बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में उन उम्मीदवारों के अनंतिम प्रवेश के लिए कोई निषेध नहीं था, जिन्होंने बीए अंतिम परीक्षा दी थी और उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया था। इसके अलावा, यदि ऐसे उम्मीदवारों को उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, तो कोई कारण नहीं था कि जिन उम्मीदवारों ने अप्रैल में बीए अंतिम परीक्षा दी थी और उन्हें एक विषय में कम्पार्टमेंट में रखा गया था, उन्हें प्रवेश नहीं मिल सकता था क्योंकि छात्रों को व्यक्तिगत रूप से बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए पूरे सत्र में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें अपेक्षित शुल्क जमा करने पर किस्तों में डाक द्वारा पाठ प्राप्त करना था। इस सत्र के दौरान, ऐसे छात्रों को सितंबर में आयोजित बीए अंतिम परीक्षा (पूरक परीक्षा) उत्तीर्ण करने के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। पूरक परीक्षा में बीए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करके, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, वे अगले अप्रैल में बीएड अंतिम परीक्षा (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) लेने के पात्र होंगे।

(16) ऊपर दर्ज किए गए इन कारणों से, रिट याचिकाओं को बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है, जिसमें प्रतिवादियों को बीएड पत्राचार पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ताओं के प्रवेश को नियमित करने और उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अंतिम परीक्षा दी है जो आयोजित की जा रही है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादीके सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोगनहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करणप्रमाणिक होगा और निष्पादन औ र कार्यान्वयन के उद्देश्यके लिए उपयुक्त रहेगा ।

वरुण बंसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम